भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1680

जिसका उत्तर 08 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है।

17 अग्रहायण, 1943 (शक)

डिजिटल साक्षरता मिशन

1680. सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल साक्षरता मिशन के कार्यान्वयन की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में छह करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा डिजिटल साक्षरता योजनाओ के कवरेज को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार को डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लोगों में कम उत्साह के कारणों पर प्रतिक्रिया मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ग) : कौशल विकास और कुशल प्रतिभा का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है कि भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति प्रदान की जाती है जिसकी उद्योग को आवश्यकता होती है। डिजिटल अपनाने में और अधिक सहायता देने के लिए, मंत्रालय ने 2014 से ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित किया है। वर्ष 2014 से 2016 में, देश भर में डिजिटल साक्षरता में 52.50 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा "राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन" (एनडीएलएम) और "डिजिटल साक्षरता अभियान" (दिशा) नामक दो योजनाओं को लागू किया गया था। इन दोनों योजनाओं के तहत कुल 53.67 लाख लाभार्थियों को प्रमाणित किया गया।

इसके बाद, 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक योजना को मंजूरी दी गई थी। अब तक लगभग 5.38 करोड़ उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है और 4.56 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से लगभग 3.39 करोड़ उम्मीदवारों को इस योजना के तहत प्रमाणित किया गया है। योजना के तहत राज्यवार उपलब्धि **अनुबंध** में देखी जा सकती है।

सरकार ने डिजिटल साक्षरता योजनाओं के कवरेज को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अभियानों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, डिजिटल वैन आदि के माध्यम से डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूकता और प्रचार गतिविधियों को बढ़ाना ।
- देश भर में अछूती ग्राम पंचायतों में नए प्रशिक्षण केंद्रों की पहचान और पंजीकरण करने के प्रयास किए गए हैं ।
- कम इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुद्दों को दूर करने के लिए, दूरस्थ स्थानों पर वाईफाई-चौपाल स्थापित किए गए हैं ।
- चिन्हित राज्यों के ग्रामीण आबादी वाले जिलों में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवारों के प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए ग्रामीण स्कूलों को लगाया गया है ।

(घ) : लाभार्थियों से नामांकन के लिए इन योजनाओं को जहां कहीं भी लागू किया गया है जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी गई है ।

*****

अनुबंध

पीएमजीदिशा योजना के तहत अब तक पंजीकृत, प्रशिक्षित और अधिप्रमाणित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

क्रम संख्या	राज्य	पंजीकृत	प्रशिक्षित	प्रमाणित
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	308	109	51
2	आंध्र प्रदेश	12,13,541	9,33,786	6,61,421
3	अरुणाचल प्रदेश	3,399	1,279	880
4	असम	25,45,034	22,18,788	17,77,702
5	बिहार	57,16,626	50,10,635	36,58,014
6	चंडीगढ़*	0	0	0
7	छत्तीसगढ	24,98,702	21,54,263	16,29,634
8	दादरा और नगर हवेली	1,652	737	446
9	दमन और दीव	1,470	846	450
10	दिल्ली*	2,086	1,401	929
1 1	गोवा	4,650	3,180	2,322
12	गुजरात	23,87,245	20,71,606	15,21,815
13	हरियाणा	17,20,102	14,55,183	10,96,074
14	हिमाचल प्रदेश	3,54,939	2,59,390	1,85,625
15	जम्मू और कश्मीर	4,54,633	3,41,094	2,50,274
16	झारखंड	20,92,199	16,73,448	12,15,415
17	कर्नाटक	9,90,825	7,47,188	4,83,761
18	केरल	50,068	24,410	19,520
19	लद्दाख	17,279	13,802	9,501
20	लक्षद्वीप	94	35	0
21	मध्य प्रदेश	45,43,049	39,57,566	29,03,180
22	महाराष्ट्र	34,91,142	28,62,502	20,69,617
23	मणिपुर	10,239	5,858	3,691
24	मेघालय	1,11,847	80,610	53,896
25	मिजोरम	9,214	6,593	3,881
26	नगालैंड	5,597	4,011	2,872
27	उड़ीसा	27,15,434	22,33,186	16,93,495
28	पुदुचेरी	13,590	9,643	6,157
29	पंजाब	14,69,681	12,56,997	9,67,725
30	राजस्थान	28,74,294	23,71,583	17,28,270
31	सिक्किम	3,551	1,521	717
32	तमिलनाडु	10,14,005	8,13,078	5,81,823

33	तेलंगाना	7,23,212	5,63,842	3,93,659
34	त्रिपुरा	2,48,544	1,87,286	1,48,402
35	उत्तराखंड	6,06,354	5,00,158	3,70,433
36	उत्तर प्रदेश	1,40,30,962	1,23,28,605	92,71,740
37	पश्चिम बंगाल	18,76,201	15,24,802	11,81,633
कुल		**5,38,01,768**	**4,56,19,021**	**3,38,95,025**

***चंडीगढ़ और दिल्ली शहरी समूह में हैं, इसलिए इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।**

****